

1. केन्द्रीय वित्त मंत्री ने कल बजट पेश करते हुए कहा— हमारी अर्थव्यवस्था सभी वैश्विक अर्थव्यवस्थाओं में सबसे तेजी से बढ़ने वाली अर्थव्यवस्था है।
2. नई व्यवस्था के अंतर्गत बारह लाख रुपये तक कोई आयकर देय नहीं होगा।
3. प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी ने कहा कि केन्द्रीय बजट एक सौ चालीस करोड़ भारतीयों की आकांक्षाओं को पूरा करने के लिए सरकार की प्रतिबद्धता को दर्शाता है।
4. आज विश्व आर्द्रभूमि दिवस मनाया जा रहा है।

<><><><><><><><>

केन्द्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारामन ने कल संसद में केन्द्रीय बजट दो हजार पच्चीस-छब्बीस प्रस्तुत किया। यह एनडीए सरकार के तीसरे कार्यकाल का पहला बजट है। बजट पेश करते हुए वित्त मंत्री ने कहा कि इसका लक्ष्य विकास में तेजी लाना, समावेशी विकास सुनिश्चित करना, निजी क्षेत्र में निवेश में वृद्धि और देश के मध्यम वर्ग के खर्च करने की क्षमता बढ़ाना है। उन्होंने कहा कि हमारी अर्थव्यवस्था सभी वैश्विक अर्थव्यवस्थाओं में सबसे तेजी से बढ़ने वाली अर्थव्यवस्था है। वित्त मंत्री निर्मला सीतारामन ने कहा कि मध्यम वर्ग भारत के विकास के लिए शक्ति प्रदान करता है। प्रधानमंत्री मोदी के नेतृत्व वाली सरकार ने राष्ट्र निर्माण में मध्यम वर्ग की सराहनीय ऊर्जा और क्षमता में विश्वास जताया है। वित्त मंत्री ने कहा कि नई कर व्यवस्था के अंतर्गत बारह लाख तक की आय पर कोई कर देय नहीं होगा।

बजट में विशिष्ट— दर आय जैसे पूंजीगत लाभ को छोड़कर एक लाख रुपये प्रति माह की औसत आय पर कोई कर देय नहीं होगा। वेतनभोगी करदाताओं के लिए यह सीमा पचहत्तर हजार की मानक कटौती के कारण बारह लाख पचहत्तर हजार होगी। सभी करदाताओं को फायदा पहुंचाने के लिए सभी श्रेणियों में कर स्लैब और दरों में परिवर्तन करने के प्रस्ताव हैं। बजट में औषधि और दवाओं के आयात पर राहत देने का प्रस्ताव किया गया है।

कल केन्द्रीय बजट में विशेष रूप से कैंसर, असाधारण रोगों और अन्य गंभीर जीर्ण रोगों से पीड़ित रोगियों को राहत देने के लिए छत्तीस जीवन रक्षक औषधियों और दवाओं को बुनियादी सीमा-शुल्क से पूरी तरह छूट प्राप्त दवाओं की सूची में शामिल करने का प्रस्ताव किया गया है। बजट में कृषि उत्पादकता बढ़ाने, फसल विविधीकरण और एक करोड़ 70 लाख किसानों को ऋण सुविधा प्रदान करने के लिए चुने हुए सौ जिलों में प्रधानमंत्री धन-धान्य कृषि योजना शुरू की जाएगी। किसान क्रेडिट कार्ड के माध्यम से ऋण सीमा तीन लाख रुपये से बढ़ाकर पांच लाख रुपये करने का प्रस्ताव, लघु, सूक्ष्म और मध्यम उद्यमों के वर्गीकरण के लिए निवेश की सीमा ढाई गुणा बढ़ाने और कारोबार सीमा भी दोगुनी करने का प्रस्ताव, स्टार्टअप के लिए ऋण गारंटी एक प्रतिशत इजाफे के साथ बढ़ाकर बीस करोड़ रुपये करने का प्रस्ताव है। वित्तमंत्री ने कहा कि राष्ट्रीय खिलौना कार्य योजना के आधार पर, देश को 'वैश्विक खिलौना केंद्र' बनाने की योजना कार्यान्वित की जाएगी। इस योजना से 'मेड इन इंडिया' ब्रांड का प्रतिनिधित्व करने वाले उच्च गुणवत्ता वाले अनूठे, नवीन और पर्यावरण अनुकूल खिलौने बनेंगे। वित्त मंत्री ने कहा कि सरकार एक संशोधित उड़ान स्कीम शुरू करेगी ताकि अगले दस वर्षों में एक सौ बीस नए गंतव्यों के साथ क्षेत्रीय कनेक्टिविटी को बढ़ाया जा सके और चार करोड़ यात्रियों को ऐसी परिवहन सुविधा दी जा सके।

<><><><><><><><>

